दैनिक जागरण
गुरुवार 23 मई 2019

दैनिक जागरण

विचार कर्म का बीज है

अलोकतांत्रिक आचरण

विभिन्न विपक्षी नेताओं की ओर से ईवीएम को लेकर जैसे शरारत भरे बयान दिए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राज्यों को ऐसे निर्देश देना आवश्यक हो गया था कि मतगणना के वक्त कहीं पर किसी तरह की हिंसा न होने पाए। मतगणना के दौरान हिंसा का अंदेशा इसलिए उभर आया है, क्योंकि कई विपक्षी नेता खुले आम उत्पात मचाने की धमकियां दे रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक्जिट पोल के आंकड़ों को चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की साजिश करार देते हुए खून की नदियां बहाने की बात की तो ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि चुनाव आयोग दंगे कराने और देश को गृहयुद्ध में धकेलने का काम कर रहा है। इसकी भी अनदेखी न करें कि ऐसे बेजा बयानों के बीच ईवीएम को संदिग्ध बताने का सिलसिला कायम है। ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पहले चुनाव आयोग के समक्ष बेजा मांगें रखी जाती हैं और फिर उन्हें ठुकराए जाने पर अन्याय होने का शोर मचाया जाता है। चिंताजनक यह है कि यह काम बड़े नेता भी करने में लगे हुए हैं। वे एक्जिट पोल को तो किसी साजिश का हिस्सा बता ही रहे हैं, यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि ईवीएम अब भरोसेमंद नहीं रह गई हैं। समझना कठिन है कि जब इसके पहले मतदान बाद पर्चियों की गिनती मतगणना के बाद ही होती रही है तो फिर यह मांग क्यों की जा रही है कि इस बार पहले इन पर्चियों को गिना जाए? कहीं इसलिए तो नहीं कि अगर कोई विसंगति दिखे तो हंगामा खड़ा करने में आसानी हो?

यह लज्जा की बात है कि वे विपक्षी नेता भी जानबूझकर ईवीएम को बदनाम करते हुए दिख रहे हैं जो इसी मशीन के सहारे अतीत में सत्ता हासिल कर चुके हैं? वे ऐसा तब कर रहे हैं जब बीते कुछ वर्षों में ईवीएम को और अधिक विश्वसनीय बनाने का काम किया गया है। हार-जीत चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन यह पहली बार है जब हार की आशंका से ईवीएम और चुनाव आयोग के साथ भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ईवीएम विरोधी अभियान को तूल दे रहे नेता अपने प्रलाप से देश को नीचा दिखाने के साथ ही मतदाताओं का भी निरादर करने में लगे हुए हैं। ऐसा करके वे अपनी अपरिपक्वता का ही परिचय दे रहे हैं। यह खेद की बात है कि बिना किसी सुबूत ईवीएम पर संदेह जताने वाले नेताओं के सुर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपना सुर मिला दिया। आखिर उन्हें यह कहने की क्या जरूरत थी कि जनादेश को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाए? यदि किसी का मकसद ही बेवजह के सवाल खड़े करना और अटकलबाजी करना हो तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत संतुष्ट नहीं कर सकती। अच्छा होता कि पूर्व राष्ट्रपति रुदन कर रहे विपक्ष को हिदायत देना बेहतर समझते।

चुनाव नतीजे का असर

सभी की नजर गुरुवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे पर है, परंतु पश्चिम बंगाल में इस चुनाव नतीजे का दूरगामी असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एक्जिट पोल में बंगाल में तृणमूल के पिछड़ने एवं भाजपा की सीटें बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है, वह काफी अहम है। वर्तमान लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि बंगाल में भाजपा सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे रही हो। यहां शुरू में सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं वामदलों के बीच लड़ाई रही। इसके बाद सत्तारूढ़ वामदलों एवं कांग्रेस। बाद में कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस बनाई तो वामदल एवं तृणमूल के बीच लड़ाई होने लगी। इसके बाद 2011 में तृणमूल सत्तारूढ़ हुई तो 2016 तक लड़ाई में वाममोर्चा एवं कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी दल थे, परंतु 2017 के बाद स्थिति बदलती गई और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस एवं वामपंथी दल हाशिए पर हैं और अब लड़ाई तृणमूल एवं भाजपा के बीच हो रही है। गुरुवार को बंगाल की धरती पर कमल (भाजपा) या जोड़ा फूल (तृणमूल) खिलता है यह काफी अहम हो गया है। यहीं से बंगाल की सियासत में नई तारीख लिखी जाएगी, क्योंकि 2011 के बाद से तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। दिन प्रति दिन, चुनाव दर चुनाव तृणमूल मजबूत होती गई, परंतु इस बार पिछले आठ वर्षों में तृणमूल को कड़ी चुनौती मिली है। यदि भाजपा अपनी दो सीटों की संख्या को बढ़ा कर दस के पार पहुंचा देती है तो 2021 विधानसभा चुनाव में तृणमूल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए यह चुनाव नतीजे बंगाल की राजनीतिक भविष्य के लिए काफी अहम और निर्णायक हैं, क्योंकि भाजपा भी उसी राह पर है जहां से तृणमूल ने वाम शासन का अंत किया था। 2008 के पंचायत चुनाव से तृणमूल ने पकड़ मजबूत करनी शुरू की और 2009 लोकसभा चुनाव में 19 सीटें जीती और 2011 में सत्ता को पलट दिया। ठीक उसी तरह से भाजपा ने पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में पकड़ मजबूत की है और अब 2019 को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को किस का मंगल होता है और किसका अमंगल?

नई सरकार की चुनौतियां

धर्मकीर्ति जोशी

नई सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को तेजी देने की होगी जिसकी चाल पिछले कुछ वक्त से सुस्त सी पड़ गई है

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय कुछ चुनौतियों से जूझ रही है। इन चुनौतियों से निपटना नई सरकार के लिए आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य होगा। जनादेश हासिल करने के बाद सरकार के सामने उन वादों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी होती है जिनके दम पर वह सत्ता में आती है। ये वादे संसाधनों के बिना पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में सरकार के सामने यह दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है कि वह अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के साथ ही जनता की अपेक्षाओं-आकांक्षाओं पर भी खरी उतरे। वास्तव में यह कोई विरोधाभास नहीं। अगर अर्थव्यवस्था की तस्वीर बेहतर होगी तो सरकार की झोली भी भरी होगी। स्वाभाविक है कि इससे सरकार के पास खर्च करने की गुंजाइश भी बढ़ती है। नई सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को तेजी देने की होगी जिसकी चाल पिछले कुछ वक्त से सुस्त सी पड़ गई है। हालांकि इसके लिए घरेलू कारकों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय पहलू भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत पर अटक गई। यह दर पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान औसतन सात फीसद वृद्धि से कम थी जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसके बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन यह भारत की संभावनाओं के मुकाबले अपेक्षाकृत कमतर है। वैश्विक अनिश्चितताओं से जहां निर्यात में आई गिरावट ने आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार कुछ कुंद की है वहीं घरेलू स्तर पर उपभोग घटने से भी आर्थिक चाल निस्तेज पड़ी है। वाहनों से लेकर अन्य कई वस्तुओं के उपभोग में आई कमी से इसकी पुष्टि भी होती है। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र का निवेश भी अटका हुआ है। ऐसे में सरकार को आगे आकर मोर्चा संभालना होगा। इसके लिए सरकार को बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना होगा जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकें। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी खर्च बढ़ाने से वित्तीय अनुशासन की स्थिति न बिगड़ जाए। इसके लिए सब्सिडी खर्च को भी तार्किक बनाना होगा। मौजूदा सरकार ने इस कड़ी में कई रिसाव रोके हैं जिन्हें आगे और चुस्त बनाना होगा। खर्च बढ़ाने के लिए सरकार को अधिक संसाधन भी जुटाने होंगे। इस दिशा में विनिवेश की राह पकड़ी जा सकती है तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की परिसंपत्तियों को भी भुनाया जा सकता है। राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ और नए कदम भी उठाने होंगे। यदि संसाधन जुटाए बिना ही खर्च बढ़ा दिया गया तो राजकोषीय घाटे का दायरा बढ़ जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर अच्छे संकेत नहीं जाएंगे। इससे देश में होने वाले निवेश से लेकर रुपये की चाल पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

किसी भी नई सरकार के लिए सुधारों का काम कुछ आसान होता है, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद राजनीतिक जोखिम कम होने से उसके पास साहसिक फैसले लेने की गुंजाइश होती है। मोदी सरकार ने कई अहम सुधार किए हैं, लेकिन वे अभी भी संक्रमण काल में हैं। जैसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जिसमें समय के साथ काफी संशोधन किए गए हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे में लाना और दरों के मोर्चे पर भी कुछ काम किया जाना शेष है। इसी तरह दीवालिया संहिता भी एक अहम सुधार है, लेकिन इसमें भी अभी तक वित्तीय क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। अभी भी भूमि सुधारों और श्रम सुधारों को मूर्त रूप दिया जाना बाकी है। चूंकि इनमें राज्य सरकारें भी अहम अंशभागी हैं तो नई केंद्र सरकार को चाहिए होगा कि वह इस कवायद में प्रोत्साहक की भूमिका निभाए। कुल मिलाकर नई सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नए सुधारों को लागू करने के साथ पहले किए जा चुके सुधारों की निरंतरता को कायम रखे।

अवधेश राजपूत

देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खेती से जुड़ा हुआ है और किसानों की खराब हालत भी किसी से छिपी नहीं रही। इसलिए सरकार को कृषि और किसानों की भलाई के लिए भी अविलंब कदम उठाने होंगे। कृषि क्षेत्र लंबे समय से सुधारों की बाट जोह रहा है। इसकी कायापलट देश की एक बड़ी आबादी का जीवन बेहतर बनाने में सक्षम है। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र को कृषि के साथ जोड़े। चूंकि काफी मात्रा में खाद्य उत्पाद बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। इसलिए यह संभव बनाया जाए कि खाद्य प्रसंस्करण का दायरा बढ़ाकर उसमें उनका इस्तेमाल किया जाए। केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि सुधारों को अमली जामा पहनाए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए। वैसे तो भारत और चीन के पास कृषि योग्य भूमि बराबर है, फिर भी चीन का उत्पादन भारत से दोगुना अधिक है। ऐसे में अगर उत्पादन बढ़ता है तो उद्योगों के लिए भी अतिरिक्त जमीन आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी।

देश में रोजगार भी नई सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। रोजगार के मोर्चे पर फिलहाल उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखती। ऐसे में नई सरकार को तात्कालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपाय आजमाने होंगे। तात्कालिक उपायों में मनरेगा जैसी योजनाएं अहम होंगी तो दीर्घावधिक योजनाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। इसके लिए विनिर्माण में कपड़ा, वाहन, चमड़ा और सेवा में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे श्रम आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बदलते वक्त के साथ ऑटोमेशन को अपनाया जा रहा है। इससे परंपरागत नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, लेकिन इससे नई तकनीकी नौकरियों की राह भी खुलेगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर सहित तमाम घटनाक्रम अनिश्चितता बढ़ाने वाले हैं। इसका असर निर्यात और विदेशी निवेश, दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में नई सरकार के सामने घरेलू स्थायित्व बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसमें दरार राजकोषीय घाटे पर दबाव से लेकर रुपये की सेहत बिगाड़ सकती है। हालांकि यह वैश्विक संकट भारत के लिए कुछ अवसर भी बना सकता है, क्योंकि अमेरिका-चीन दोनों को नए व्यापार साझेदार तलाशने होंगे। ऐसी स्थिति में ट्रेड डायवर्जन होता है। नई सरकार को इस अवसर को भुनाने की कोशिश करनी होगी। इसका निर्यात और निवेश दोनों पर अनुकूल असर होगा।

महंगाई को लेकर नई सरकार को कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि मानसून खराब रहा और कच्चे तेल के दाम चढ़ते गए तब जरूर इस बारे में कुछ सोचना पड़ सकता है। फिलहाल तो नई सरकार के आर्थिक एजेंडे में यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह वित्तीय अनुशासन कायम रखते हुए खर्च बढ़ाए ताकि मांग में सुधार हो सके और सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखे। कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दे और घरेलू स्थिरता की ऐसी क्षमता विकसित करे जिस पर वैश्विक अस्थिरता कम से कम असर करे।

(लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

हिंसक राजनीति से बचने की चुनौती

तरुण विजय

पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां यह लगता है कि गणतंत्र और राजतंत्र में फर्क ही मिट गया है

इन दिनों पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह तानाशाही के बाद जन्मे किसी नवजात गणराज्य का क्रंदन ही लगता है। वहां चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा जारी है। इतना ही नहीं, इस बात का गहन अंदेशा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में नए सिरे से हिंसा भड़क सकती है। क्या इसे रोका नहीं जाना चाहिए? चुनाव नतीजे कुछ भी हों, सारे देश को इस पर विचार करना होगा कि बंगाल हिंसा की राजनीति के दुष्चक्र से कैसे मुक्त हो? यह दुख की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाला हमारा देश उन नेताओं के भरोसे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जिनका आचरण कहीं से भी लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के अनुकूल नहीं दिखता। आज पश्चिम बंगाल में भगवा वस्त्रधारी कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों का शिकार हो रहे हैं। जैसे वंदे मातरम से अंग्रेज कभी चिढ़ते थे वैसे ही आज जय श्रीराम के नारे से वहां की कथित सेक्युलर सत्ता चिढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में कोई जय श्रीराम बोल दे रहा है तो उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। वहां कोई तृणमूल प्रमुख का कार्टून या मीम भी बना दे तो पुलिस पकड़ लेती है। विडंबना यह है कि इस पर भी खुद को सेक्युलर-लिबरल कहने वाले मौन धारण करना पसंद करते हैं या फिर यह सिद्ध करना कि जयश्री राम बोलना सांप्रदायिक है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में भाजपा और संघ के कई कार्यकर्ता मार डाले गए। ऐसी आतंक की कथाएं जब अखबारों में छपती हैं तो आश्चर्य होता है कि यह पढ़े-लिखे नेताओं का चुनाव हो रहा था या पाषाणकालीन मानवों का हिंसक खेल हो रहा था?

वास्तव में चुनाव लोकतंत्र की परंपरा है जो कार्यक्रमों, नीतियों और भविष्य के दृष्टिपथ को सामने रखकर लड़ा जाता है। भारत में ऐसे अनेक रोमांचक और युग प्रवर्तक चुनाव हुए हैं जिनमें 1977 के आपातकाल के तुरंत बाद वाला निर्वाचन भी शामिल है, लेकिन ऐसी गाली-गलौच और हिंसा पहले कभी देखने को नहीं मिली जैसी इस बार के लोकसभा चुनावों में देखने को मिली। प्रधानमंत्री को चोर कहना तो जैसे चना मुरमुरा खाने जैसा साधारण कृत्य हो गया। यह भी अजीब है कि सर्वोच्च न्यायालय से झूठ के लिए माफी मांगने के बाद भी चोर-चोर कहने वालों ने लज्जा का परिचय नहीं दिया। क्या यह देश के संघीय ढांचे के लिए कम घातक है कि एक तरफ बंगाल में तृणमूल की अगुआई वाली सत्ता षड्यंत्र और राष्ट्रघात की मानसिकता से आ रहे घुसपैठियों को सादर सम्मान सहित राशन कार्ड जैसी सुविधाएं देना पसंद कर रही है और दूसरी ओर दिल्ली और शेष देश से बंगाल आने वाले भारतीयों को बाहरी गुंडा कहकर उन्हें बाहर फेंकने की धमकी दे रही है। उद्योगहीनता,

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में लिप्त शीर्ष नेता और दुष्कर्म एवं किसानों की आत्महत्याएं आज जिस बंगाल की मुख्य पहचान बन गई हैं वहां लोकतांत्रिक पार्टी का अर्थ है एक नेता का एकाधिकारवाद। यहां सत्ताधारी दल में नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी प्रकार के भिन्न मत की अनुपस्थिति दिखती है।

पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां लगता है कि गणतंत्र और राजतंत्र में फर्क ही मिट गया है। इसके बावजूद बौद्धिक समाज प्रतिशोध के डर से सिर्फ बाबुगीरी में काम कर रहा है। इसी बंगाल में जब टाटा ने अपना कारखाना लगाना चाहा था तो वर्तमान सेक्युलर सत्ता के सूत्रधार ने हजारों-लाखों को रोजगार देने वाले उस उपक्रम को प्रदेश से बाहर जाने में एक भूमिका निभाई थी। हालांकि तब माकपा का शासन था। आज यह कल्पना करना भी कठिन है कि यह वही बंगाल है जहां कभी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाषचंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुष हुए थे। इसी बंगाल के नौजवानों ने कभी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आज जिस प्रकार भगवा वस्त्रधारियों का कथित सेक्युलर सत्ता द्वारा निरंकुश दमन हो रहा है उसने एक समय निरंकुश ब्रिटिश सत्ता द्वारा धर्म ध्वजा लेकर खड़े हुए संन्यासी विद्रोह पर हमले की स्मृति जगा दी।

आज के बंगाल के माहौल में 1882 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास याद आता है जो 18वीं सदी के उस बंगाल की क्रांति गाथा थी जो अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ एक संन्यासी विद्रोह के रूप में फूट पड़ी थी। यह वही आनंद मठ है जिसने हमें वंदे मातरम गीत दिया जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों क्रांतिकारियों के अधरों पर लहरा। यह गीत अलग से लिखा हुआ नहीं है, बल्कि आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है। इस पर 1952 में पृथ्वी राज कपूर के नायकत्व में आनंद मठ नाम से एक श्वेत श्याम फिल्म भी बनी जिसमें लता मंगेशकर द्वारा गाया संपूर्ण वंदे मातरम गीत युद्ध की धुन पर है। उस समय भी एक सत्ता थी जो निरंकुशता और तानाशाही का प्रतीक थी और एक प्रजा थी जो अपने धर्म, संस्कृति तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर लड़ रही थी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति आनंद मठ प्रत्येक दल और विचारधारा को मानने वाले हर उस भारतीय को पढ़नी चाहिए जो भारत की वेदना से परिचित होना चाहता है। इसमें अकाल पीड़ित गांव से महेंद्र, उनकी पत्नी कल्याणी, आनंद मठ के गुरु के रूप में प्रखर राष्ट्रीय विचार वाले योद्धा गुरु सत्यानंद, युवा संन्यासी और शस्त्र एवं शास्त्र में पारंगत जीवानंद और दमन से लड़ने वाली युवती शांति के चरित्र एक शताब्दी से भी अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को झकझोरते और प्रेरित करते रहे। आनंद मठ फिल्म में पृथ्वी राज कपूर की गंभीर वाणी राष्ट्र प्रेमियों के हृदय के संताप और राष्ट्रघाती तत्वों के निर्मूलन का संदेश देती है। यह फिल्म देश के हर विद्यालय में दिखाई जानी चाहिए। प्रश्न उठता है कि आज हिंदू बहुसंख्यक देश में ही हिंदू भावनाओं पर प्रहार राजनीतिक दृष्टि से किसे लाभप्रद लगना चाहिए? जिन लोगों ने विदेशी आततायियों के खिलाफ अपने धर्म और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष किया वे यदि आज भी अपने धर्म और विचार की रक्षा के लिए मारे जाएं तो क्या आजाद भारत में यह स्थिति स्वीकार होनी चाहिए? इस स्थिति को बदलने के लिए उठा हर कदम आनंद मठ का ही प्रतिरूप है।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर

अंतर्मन में निहित भक्ति और जीवन को पवित्र एवं आध्यात्मिक बनाने की प्रबल शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद की सारी व्यवस्था ईश्वर स्वयं कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि अनेक अपराधियों का हृदय परिवर्तन हुआ और वे अतीत से नाता तोड़कर ईश्वर की शरण में चले गए और सर्वोत्तम मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जब ऐसे कठोर अपराधी भी इतने अल्प समय में एक पवित्र आध्यात्मिक मनुष्य बन गए, तब कोई कारण नहीं है कि दूसरा भी क्यों नहीं ईश्वर की यह कृपा प्राप्त कर सकता है। सभी स्त्री-पुरुष ईश्वर की यह कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों के प्रति ईश्वर का कर्तव्य है, उसी प्रकार मनुष्यों का कर्तव्य भी ईश्वर के प्रति है। मनुष्यों को केवल वह कर्म करना है जो ईश्वर को आनंद देता है। ईश्वर कभी भी पापी और पुण्यात्मा के बीच भेद नहीं करते। यदि ईश्वर चाहें तो वह तथाकथित पापी मनुष्य को भी क्षण भर में एक महान भक्त बना सकते हैं। अनेक दोषों के बावजूद मनुष्य प्राणी के रूप में ईश्वर की महान देन है।

प्रत्येक वस्तु दैवीय सृष्टि है और सभी में एक न एक दिन पूर्णता प्राप्त करने की संभावना है। हम अभी जो कुछ हैं, वह हमारे पूर्व के विचारों और कर्मों का परिणाम है और भविष्य में हम जो कुछ होंगे, वह हमारे पूर्व के विचारों और कर्मों का परिणाम होगा। हमारे अतीत का कर्म ही हमारे वर्तमान को निर्धारित करता है और हमारे वर्तमान के विचार और कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। कोई भी सांसारिक पदार्थ या मनुष्य हमारा स्थायी साथी या संबंधी नहीं है। इसलिए हमें किसी पर विलाप नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य मानते हैं कि एकमात्र ईश्वरानुभूति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।

जब मनुष्य सभी स्थूल पदार्थों से अपनी मानसिक वृत्तियों को वापस खींच लेता है और उसे ईश्वर की ओर मोड़ देता है, तब उसे अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। प्रत्येक साधक, चाहे उसका अतीत कितना भी मलिन और निंदनीय क्यों न रहा हो, आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने का अधिकारी है। साधक जब अपने चारों ओर दैवीय वातावरण में दैवीय अस्तित्व की तरंगों को महसूस करता है, तब वह ईश्वर की अनुभूति करता है। इस तरह की अनुभूति परमानंद का अनुभव कराती है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव

मताली जैन

एक राष्ट्र तभी तरक्की करता है, जब उसके नागरिक स्वस्थ हों और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं

वर्तमान में भारत में बेहतर स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। लैंसेट पत्रिका के एक शोध के अनुसार सुरक्षित और पोषक भोजन नहीं लेने के कारण भारतीय किशोरों की सीखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। शोध में यह बात सामने आई है कि शुरुआती उम्र में पोषक भोजन की कमी व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। उसके अनुसार भारत में पौष्टिक आहार की कमी के चलते हर साल सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर अनुमानतः पांच में से एक व्यक्ति की मौत पौष्टिक आहार और पोषक तत्वों की कमी से जुड़ी है। इतना ही नहीं, पौष्टिक आहार का अभाव विश्वभर में कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है।

एक ओर जहां पौष्टिक आहार की कमी एवं खानपान में असंतुलन आदि के कारण व्यक्ति कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को गहरा आघात पहुंचाती है। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार हार्ट अटैक के सिर्फ 40 फीसद मरीजों को धमनियों में ब्लड क्लॉट दूर करने की दवाएं मिल पाती हैं। सिर्फ हृदय रोगी ही स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम नहीं हैं। कमोबेश हर स्वास्थ्य समस्या के दौरान व्यक्ति को इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 10189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस तरह भारत में छह लाख डॉक्टरों की कमी है। इतना ही नहीं, देश में हर 483 लोगों पर एक नर्स है, यानी 20 लाख नर्सों की भी कमी है। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी (सीडीडीईपी) की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर साल 57 लाख ऐसे लोगों की मौत होती है, जिन्हें एंटीबॉयोटिक दवाओं के जरिए बचाया जा सकता था। ये मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में ज्यादा होती हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो यहां पर स्थिति और भी अधिक चिंतनीय है। भारत में समय पर सही दवा न मिलने से लोग असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। साथ ही यह उनकी जेब पर भी काफी भारी पड़ता है। सीडीडीईपी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोगों को बीमारी पर होने वाला 65 फीसद खर्च खुद उठाना पड़ता है। इसके कारण हर साल करीबन 5.7 करोड़ लोग गरीबी की खाई में गिरते चले जाते हैं और उनका आगे का जीवन बेहद कष्टकारी एवं अभावपूर्ण तरीके से गुजरता है।

एक राष्ट्र तभी तरक्की करता है, जब उसके नागरिक स्वस्थ हों और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। देश को स्वस्थ बनाने का एकमात्र उपाय है जागरूकता। अशिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ है। अब समय है कि लोगों का रुझान पौष्टिक आहार के प्रति बढ़ाने एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च के बोझ से व्यक्ति एवं सरकार दोनों को ही राहत मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

युवा पीढ़ी का दायित्व

मूर्तिभंजन के बाद याद आए ईश्वरचंद्र शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजीव सचान ने कहा है कि कोलकाता के एक कॉलेज में समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने के बाद ही देश को उनके बारे में जानने का मौका मिला है। सबसे पहले तो यह कहना उचित होगा कि अगर कोई महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बताए राह पर नहीं चल सकता या उनसे प्रेरणा लेकर समाज और देश के लिए अच्छे काम नहीं कर सकता तो कम से कम वह उनका अपमान भी न करे। यह देश के लिए बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि कॉलेज के अंदर कुछ शरारती तत्वों ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ दिया। इससे पता चलता है कि आज की युवा पीढ़ी किस गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा दोष ऐसे शरारती तत्वों के माता-पिता और अध्यापकों का है जो भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार और देशभक्ति का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अगर इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो उसमें बहुत से ऐसे सच सामने आएंगे, जिनमें यह जिक्र होगा कि किस तरह हमारे देश के बहुत से नौजवानों ने अपनी मौज-मस्ती की उम्र में देश और समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना सबकुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अफसोस आज आजाद देश के कुछ युवा राजनीतिक दलों की गंदी राजनीति के झांसे में आकर गलत काम करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। शिक्षा संस्थानों को भी राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

आ गई वह घड़ी

लोकतंत्र के महापर्व के सात पड़ाव पूर्ण होने के साथ आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सबके मन में एक विचार था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और किस पार्टी का होगा? वह बृहस्पतिवार को स्पष्ट होने वाला है। वहीं ईवीएम जिसे बरसों से अनेकों विपक्षी पार्टियां संदेह के घेरे में घेरती आई हैं, इसके रुकने का सिलसिला आज भी नाम नहीं ले रहा है। कतिपय राजनेताओं का तो यह तक कहना है कि यदि ईवीएम से छेड़छाड़ कर सत्ताधारी पार्टी मतगणना का रुख अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करती है तो सड़कों पर खून बहेगा। इसके प्रारंभिक परिणाम हमें गाजीपुर, कन्नौज और झांसी में स्ट्रांग रूम के बाहर हुए हंगामे के रूप में देखने को मिले हैं। इसके साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए इसके विरोध में एक बार फिर लामबंद होने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि स्ट्रांग रूम के बाहर पाई गईं ईवीएम का मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रांग रूम के बाहर पाई गईं ईवीएम को अतिरिक्त ईवीएम का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को अचूक बताया है। वहीं ईवीएम के वीवीपैट से शत प्रतिशत मिलान वाली याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। मतगणना से पहले एक्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए हंगामा होना स्वाभाविक है। और जिसके लिए विपक्षी दलों के पास ईवीएम के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि यदि विपक्ष बुरी तरह हारा तो इसका ठीकरा पूरी तरह ईवीएम के सिर ही फोड़ेगा।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

मेलबाक्स

परिणाम की प्रतीक्षा

दैनिक जागरण में ईवीएम का रोना शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय आलेख में सही लिखा गया है कि विपक्षी दल अपनी संभावित हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की पेशबंदी कर रहे हैं। चुनाव और खेल में हार-जीत होती रहती है, लेकिन हार के लिए रेफरी को दोष देना अनुचित है। खेल का तो यही मंत्र है कि गलती से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राजनीति ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी अपनी पराजय का सेहरा दूसरे के सिर पर बांध देता है। लगता है, राजनीति में जय-पराजय को समभाव से लेने के दिन अब लद गए। यदि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर अंगुली उठती है तो सारी व्यवस्था ही बेमानी हो जाएगी। जब चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन में हेर-फेर करने की चुनौती दी थी तब किसी ने भी उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लिए यही उचित है कि वह परिणाम की प्रतीक्षा करे और जनादेश का सम्मान करना सीखे।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।